

भारतीय कृषक समाज एवं हरित क्रान्ति

डॉ० मनोज कुमार मिश्र*

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समुचित विकास करने के लिए आवश्यक है कि कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जाये। भारतीय नियोजनकर्ताओं ने कृषि में वृद्धि करने के लिए समय-समय पर अनेक प्रयास किए हैं। इन प्रयासों में 'हरित क्रान्ति' केवल एक प्रयास न होकर बल्कि एक आन्दोलन है। 'हरित क्रान्ति' कृषि विकास के क्षेत्र में एक ऐसा वट वृक्ष है जिसके तने के रूप में अनेक कार्यक्रम कृषि विकास के लिए कार्यरत हैं और इन सभी कार्यक्रमों का समन्वित रूप ही 'हरित क्रान्ति' है। ब्रिटिश शासन के पश्चात् स्वतंत्र भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के अनेक कार्यक्रम जैसे— पंचवर्षीय योजनाएँ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण आदि चलाए गए लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इसमें उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। फलतः राष्ट्र को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1966-67 में कृषि में एक प्रौद्योगिकीय नवाचार प्रारम्भ किया जिसे 'हरित क्रान्ति' कहा गया और जिसका उद्देश्य अधिक पैदावार देने वाले बीजों, सिंचाई के उन्नत साधनों, कीटनाशक दवाइयों, रासायनिक उर्वरकों आदि के प्रयोग द्वारा कृषि क्षेत्र में भारत को आत्म-निर्भर बनाना था।

'हरित क्रान्ति'के अन्तर्गत कृषि विकास की एक नयी नीति का प्रादुर्भाव हुआ जिसके प्रथम चरण के रूप में सन् 1960-61 में तीन जनपदों में 'गहन कृषि जिला कार्यक्रम' (Intensive Agricultural District Programme) अपनाया गया। बाद में कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए अन्य जनपदों में भी इसका विस्तार कर दिया गया। इस चरण में उन जिलों को लिया गया था जिनमें विकास की अधिक सम्भावनाएं थीं अर्थात् उनमें सिंचाई की पर्याप्त सुविधायें थी या पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती थी एवं प्राकृतिक आपदाओं की सम्भावनाएं न्यूनतम थीं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि के विभिन्न साधनों (सुधरे हुए कृषि के तरीके, बीज, खाद, दवा, औजार एवं सिंचाई) का एक साथ प्रयोग किया जाता है। बाद में इस कार्यक्रम को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कार्यक्रम के क्षेत्र को सीमित करके इसे 'गहन कृषि-क्षेत्रीय कार्यक्रम' (Intensive Agricultural Area Programme) का नाम दिया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चुनी हुई या विशिष्ट फसलों के विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया। इसमें कृषि-उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से किसानों की कृषि की नई तकनीक के ज्ञान, साख व उत्पादन के साधनों तक पहुँच बनाने का प्रयास किया गया।

कृषि से सम्बन्धित इन दोनों की कार्यक्रमों का कार्यक्षेत्र मात्र फसलों की प्रचलित किस्मों तक ही सीमित था। इनमें फसलों की नई किस्मों का आरम्भ नहीं हो पाया था। खाद व अन्य साधनों के प्रयोग के बावजूद फसलों की प्रचलित किस्मों से पैदावार में अधिक वृद्धि नहीं हो पायी थी। अतः देश के व्यापक क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली किस्में सर्वप्रथम 1966 में खरीफ की फसल से ही प्रारम्भ की गई। यहीं से 'हरित क्रान्ति' का शुभारम्भ माना जाता है।

देश के कृषक एवं कृषि दोनों ही अर्थव्यवस्था के मजबूत आधार माने जाते हैं, इसलिए 'कृषक अन्नदाता' (Grain Giver) कहा जाता है। अतः "किसान की सेवा ईश्वर की सेवा है।" देश में लगभग दो-तिहाई लोगों को रोजगार के स्रोत मुहैया कराने, खाद्य सुरक्षा प्रदान करने तथा बड़े स्तर पर निर्यात बढ़ाने में अब इसका कोई जवाब नहीं। इसलिए कृषि-उत्पादों की बढ़ोत्तरी के साथ कृषकों की खुशहाली सम्पन्नता एवं उत्पादकता पर देश की सुख समृद्धि भी काफी निर्भर करती है। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक देश में हरित क्रान्ति के जनक एवं 'राष्ट्रीय किसान आयोग' के अध्यक्ष 'डॉ० एम०एस० स्वामीनाथन' ने तो यहां तक कहा है कि "कृषि से ज्यादा ध्यान अब कृषकों पर दिया जाना चाहिए। कृषकों की वास्तविक आय यदि बढ़ी तो कृषि विकास का रास्ता स्वतः ही तैयार हो जायेगा।" यदि देश के कृषक खुशहाल होंगे, तो मुल्क में और सबका कारोबार भी सही चलेगा। इसीलिए हरित क्रान्ति में निम्नलिखित तत्वों को शामिल किया गया—

* असिस्टेन्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, गनपत सहाय पी०जी० कालेज, सुलतानपुर (उ०प्र०)

1. **अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम** : अधिक उपज देने वाली फसलों के कार्यक्रमों को 1966-67 में विस्तृत व उपयुक्त भूमि में लागू किया गया इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक छः फसलों—धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी का चयन किया गया है। जिसमें से सर्वाधिक सफलता गेहूँ के उत्पादन में मिली है।
2. **बहु-फसल कार्यक्रम** : हरित क्रान्ति में बहु फसल कार्यक्रम को भी सम्मिलित किया गया है जिसमें कम समय में पक कर तैयार हो जाने वाली किस्मों की फसलों की खेती की जाती है। इसके लिए धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें, तिलहन, तथा अनेक सब्जियों की अल्पावधि वाली किस्में विकसित की गईं।
3. **लघु सिंचाई पर बल** : हरित क्रान्ति में लघु सिंचाई के कार्यक्रमों को विशिष्ट प्राथमिकता दी गई। इनके अन्तर्गत भूगर्भ जल योजनाओं जैसे— पम्प सेट, निजी ट्यूब-वेल तथा राजकीय ट्यूब-वेल आदि का काफी विस्तार किया गया।
4. **उर्वरकों के प्रयोग पर अधिक बल** : इसमें फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग पर विशेष जोर दिया गया। फलतः नाइट्रोजन, फॉस्फेट एवं पोटैश के उपयोग में विशेष वृद्धि हुई।
5. **विभिन्न निगमों की स्थापना** : हरित क्रान्ति के अन्तर्गत कृषि विकास के लिए विभिन्न निगमों की स्थापना की गई। ये केन्द्रीय व राज्य सरकारों के मिले-जुले उपक्रम हैं जिनका मुख्य उद्देश्य कृषि मशीनों की सप्लाई करना है। बीजों के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय बीज निगम एवं राजकीय फार्म निगम कार्यरत हैं।
6. **कृषक प्रशिक्षण एवं साक्षरता अभियान कार्यक्रम** : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों को कृषि से सम्बद्ध नवीन तकनीक का ज्ञान कराने तथा उन्नत बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद एवं कृषि औजारों के उपयोग के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है।
7. **कृषि उत्पादन का उचित मूल्य निर्धारण** : 'हरित क्रान्ति' का एक प्रमुख तत्व कृषकों को उचित मूल्य की गारण्टी प्रदान करना भी रहा है। सरकार को कृषि पदार्थों के मूल्यों के सम्बन्ध में 'कृषि लागत व मूल्य आयोग' सुझाव देता रहा है। इसके सुझावों के आधार पर समय-समय पर सरकार ने वसूली एवं खरीद के मूल्य बढ़ाये हैं। इससे कृषक उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रेरित हुए हैं।

इसके अतिरिक्त जैसे— कीटनाशकों पर बल, शुष्क कृषि का विकास, भूमि सुधार, भूमि संरक्षण पौध संरक्षण तथा पशुपालन का विकास जैसे कार्यक्रमों को भी 'हरितक्रान्ति' के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री 'पण्डित जवाहर लाल नेहरू' ने वर्ष 1948 में कृषि के महत्त्व को देखते हुए कहा था— 'सब कुछ इन्तजार कर सकता है, पर कृषि नहीं' (Everything else can wait but not Agriculture), पर इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि कृषि में राष्ट्रीय नीति बनाने तथा लागू करने में उद्योगों की तुलना में कृषि ने कुछ ज्यादा ही इन्तजार किया है।

'हरित क्रान्ति' के भारतीय कृषक समाज पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही तरह के प्रभाव पड़े हैं। खाद्यान्न में उत्पादन में वृद्धि और देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में हरित क्रान्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत में यदि हरित क्रान्ति न होती तो सम्भवतः देश को भुखमरी व अकालों का सामना करना पड़ता। इसी कारण कुछ लोगों का मानना है कि यदि भारत में 'हरितक्रान्ति' आन्दोलन आरम्भ न किया गया होता तो 'खूनी क्रान्ति', (Blood Revolution) हो जाने की सम्भावनाएं बढ़ जाती। उत्पादन में वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, वास्तविक मजदूरी में वृद्धि और गरीबी उन्मूलन भी इसका एक सामाजिक आर्थिक परिणाम रहा है। कृषकों के जीवन स्तर में सुधार भी हरित क्रान्ति का एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिणाम रहा है। इसके कारण कृषकों के स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, उपभोग आदि के स्तर में सुधार सम्भव हुआ। 'उत्सा पटनायक' के अनुसार "हरित क्रान्ति के आर्थिक आधार पर लोगों की प्रस्थिति में सुधार संभव बनाकर जाति सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था से वर्ग स्तरीकरण की व्यवस्था में परिवर्तन और उसमें गतिशीलता को संभव बनाया है।" 'दीपांकर गुप्ता' ने पश्चिमी आंध्रप्रदेश के अपने अध्ययन के आधार पर कृषकों में राजनीति चेतना के विकास को भी हरित क्रान्ति के प्रमुख सामाजिक परिणाम के रूप में दर्शाया है। जीवन-स्तर में सुधार के साथ इन कृषकों में राजनीतिक चेतना का विकास और किसान संगठन का उद्भव एक दबाव समूह के रूप में हुआ। जिसने न केवल कृषक आन्दोलन को सम्भव बनाया है बल्कि सरकार पर दबाव बनाकर कृषकों के पक्ष में लाभ प्राप्त करने और

कृषकों के जीवन स्तर सुधार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हरित क्रान्ति ने कृषकों की मानसिकता में “आधुनिकता एवं नवाचार” को ग्रहण करने की दिशा में परिवर्तन को सम्भव बनाया है जिससे भारत के ग्रामीण समाज में आधुनिकीकरण की दिशा में परिवर्तन को गति मिली है।

‘हरितक्रान्ति’ का भारतीय कृषक समाज पर कई नकारात्मक परिणाम भी दिखाई पड़ता है। जैसे इसका एक प्रभाव सामाजिक-आर्थिक प्रभाव क्षेत्रीय एवं वर्गगत विषमता में वृद्धि करना है। ‘हरित क्रान्ति’ के द्वारा विभिन्न सुविधाएं, साधन एवं अभिकरण देश के कुछ चुने हुए क्षेत्रों को ही प्रदान किये गये। इससे उन क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो विकास हुआ परन्तु बाकी क्षेत्रों जिनको ये सुविधाएं प्रदान नहीं की गई, अतः उनका विकास नहीं हो सका। ‘डा० वी० के० आर०वी० राव’ ने भी कहा था कि— “कृषि की इस नयी नीति से कृषकों में अन्तर्क्षेत्रीय समस्यायें उत्पन्न होंगी जिससे करोड़ों कृषकों में असन्तोष फैल जायेगा।” हरित क्रान्ति ने धनी एवं निर्धनों के बीच की खाई को भी बढ़ा दिया। धनी एवं बड़े-बड़े कृषकों ने हरित क्रान्ति के द्वारा प्लान की गयी सुविधाओं का विशेष लाभ उठाया, फलतः वे और धनी हो गये। इसके विपरीत निर्धन कृषक अपनी निम्न आर्थिकी के कारण उन्नत बीज, रासायनिक खाद, आधुनिक कृषि उपकरणों आदि का लाभ नहीं उठा सके फलतः उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती गयी। कृषि क्षेत्र में ‘सर्वहाराकरण’ की प्रक्रिया ठीक हुई और कृषक श्रमिकों की प्रतिशतता में वृद्धि होती गयी। एन० प्रसाद कैथलीन गफ, ई० ब्रॉस आदि के अध्ययन इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। इनका मानना है कि पंजाब के बड़े 10 प्रतिशत कृषकों को ही अधिकतम लाभ प्राप्त हुआ है।

‘हरितक्रान्ति’ में कृषि के क्षेत्र में यंत्रीकरण पर बल दिया गया है, फलतः कुछ विद्वानों का मत है कि इस क्रान्ति में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि की है। कृषकों के यंत्रीकरण से उत्पन्न बेरोजगारी एवं कृषि मजदूरों की अत्यधिक आपूर्ति ने कृषि श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में कमी को संभव बनाया है। इस संदर्भ में ‘प्रणव वर्द्धन एवं जानमैचर’ का मानना है कि कृषि मजदूरों की मजदूरी में तो वृद्धि हुई है लेकिन यह वृद्धि मजदूरी के अनुपात में कम रही है। फलतः उनकी इच्छाशक्ति में कमी आयी है। ‘हरित क्रान्ति’ ने कृषि-कार्य को महंगा कर दिया जिसके कारण छोटे कृषकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा जिसकी परिणति कृषक-असंतोष में वृद्धि, कृषि कार्य में अरुचि, वर्ग संघर्ष एवं जातीय संघर्ष के रूप में हुई। (दीपांकर गुप्ता, पी०सी० जोशी) ‘पी०सी० जोशी’ का मानना है कि— “हरित क्रान्ति ने धनी कृषकों को राजनैतिक दृष्टि से शक्तिशाली बना दिया है जिसके कारण उन्होंने भूमि सुधार कार्यों में बाधा उत्पन्न किया है। फलतः भूमि सुधार कार्यक्रम को अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई है।”

‘हरित क्रान्ति’ ने जजमानी व्यवस्था के उन्मूलन में भी प्रमुख भूमिका अदा की है। जिससे ग्रामीण भारत में विभिन्न जातियों के बीच प्रकार्यात्मक आत्मनिर्भरता समाप्त हो गयी है। हरित क्रान्ति का एक महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव भूमि के जलस्तर में गिरावट एवं भूमि की उर्वरता शक्ति में लोगों को सम्पोषणीय विकास की दिशा में विवश किया है।

नवीनतम तकनीक व अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के आने से गेहूँ का उत्पादन बढ़कर वर्ष 1967-68 में 27.5 मिलियन टन था, जो वर्ष 2013-14 में 95.9 मिलियन टन तक हो गया है, इसके पीछे गेहूँ की खेती करने वाले किसानों के प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही; इसी के साथ देश में खाद्यान्न उत्पादन के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता का संकेत नजर आया। भारत को कृषि क्षेत्र में विभिन्न तकनीकों को अपनाने के साथ ही फसल विविधीकरण को अपनाना अधिक उपयुक्त होगा। इससे वर्तमान भारतीय कृषक समाज अधिक समृद्ध होगा। ‘घाघ’ कवि/मौसमवेत्ता (1600ई० में)— गाँव देवकली, गंगा किनारे कन्नौज, उ०प्र०, दुबे ब्राह्मण ने फसल चक्र अपनाने हेतु सही कथन दिया था कि— “बारी में बारी करै, करै ईख से ईख, वो घर यूँ ही जायेगा (↓) जैसे मूरख की सीख।” अतः फसल चक्र में धान्य, दलहनी, तिलहनी, चारे वाली फसलें ली जानी चाहिये, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहेगी और उपज अच्छी होगी। हरितक्रान्ति के सकारात्मक परिणाम नकारात्मक परिणामों की अपेक्षा अधिक प्रभावी एवं महत्वपूर्ण रहे हैं। कुछ हद तक ‘सी०एच० हनुमन्त राव’ से सहमत हुआ जा सकता है जिनका कहना है कि— “हरित क्रान्ति के लाभों से गांवों के सभी वर्गों को दिशा मिली है और इससे वास्तविक मजदूरी एवं रोजगार में वृद्धि हुई है। इससे एक ही क्षेत्र के विभिन्न आय समूहों के बीच असमानताओं की तुलना में प्रादेशिक असमानता में अधिक वृद्धि हुई है। इसीलिए जहां कृषि की सांमती प्रथा नहीं पायी जाती है (जैसे— पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश) वहां ग्रामीण समुदाय के विभिन्न वर्गों में घाटा दृष्टिगत नहीं होता है।”

भारत का दो तिहाई कृषि क्षेत्र आज भी वर्षा पर निर्भर है नवीन योजनाओं के द्वारा सिंचाई के साधनों का और अधिक विकास करके कृषि उत्पादन की मानसून पर निर्भरता को कम किया जाये। हरित क्रान्ति मात्र कुछ चुनी हुई फसलों (विशेष रूप से गेहूँ) तक ही सीमित है इसको अन्य किस्म के फसलों पर भी लागू किया जाए ताकि इसका अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। देश की भूमि के 47 प्रतिशत हिस्से पर सिर्फ सात प्रतिशत भारतीयों का स्वामित्व है। इसका मतलब है कि भूमि संसाधनों के शेष 53 प्रतिशत हिस्से पर 93 प्रतिशत आबादी किसी तरह अपना पैर टिकाए हुए हैं। भूमि सुधार कार्यक्रम को कठोरता से लागू करके आय के स्रोतों के क्षेत्र में विद्यमान विषमता को दूर किया जाए और चकबन्दी योग्य द्वारा खेतों के आकार को बढ़ाकर अधिकाधिक खेती के योग्य बनाया जाय। कृषकों को कृषि कार्य से सम्बन्धित नवीनतम जानकारी एवं साधनों को उपलब्ध कराया जाए तथा इसके सम्बन्ध में उन्हें समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। **कृषि के क्षेत्र में गहन शोध कार्य एवं प्रशिक्षण** को प्रोत्साहित किया जाए तथा बायोटेक्नोलॉजी केनबीन अस्त्रों (Tissue Culture, Genetic Engineering) आदि का उपयोग किया जाए। भू-संरक्षण, जल संरक्षण, नमी-संरक्षण एवं कीट व बीमारियों से फसलों की रक्षा पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए कृषि-ऋण व्यवस्था का तार्किकीकरण एवं सरलीकरण आवश्यक है। **(स्वाथीनाथन समिति)** नवीन आर्थिक साधनों के सन्दर्भ में भी सरकार को कृषकों के हितों का ध्यान में रखना होगा। क्योंकि आर्थिक सुधार नीतियों के तहत किसानों को दी जा रही सब्सिडी में कटौती ने उनको नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

हरितक्रान्ति के द्वारा किसानों के दृष्टिकोण में व्यापक बदलाव आया है। 'लैजिस्की' के अनुसार "जहां कहीं भी नई तकनीकें उपलब्ध हैं कोई किसान उनके महत्व को अस्वीकार नहीं करता। बेहतर कृषि विधियों तथा बेहतर जीवन-स्तर की इच्छा न केवल नई उत्पादन तकनीकों का प्रयोग करने वाले एक छोटे से धनी वर्ग तक सीमित है बल्कि उन लाखों कृषकों में भी फैल गई है जिन्होंने अभी तक इन्हें नहीं अपनाया है और जिनके लिए बेहतर जीवन-स्तर अभी एक सपना है।" यदि हम विकास योजनाओं का लाभ मुख्यतः छोटे किसानों को देकर ग्रामीण स्वराज्य का स्वप्न साकार करना चाहते हैं तो निश्चित ही हमें बड़े भू-स्वामियों के प्रभाव-क्षेत्र से बाहर निकल कर योजनओं के बारे में सीमान्त कृषकों के दृष्टिकोण से विचार करना होगा। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 21वीं सदी में देश में 'दूसरी हरित क्रान्ति' लाने हेतु विगत 6 दशकों में हुए कृषि क्षेत्र में अनुसंधानों के परिणामों एवं सुझावों को अपनाना होगा, तभी देश की निरन्तर तेज गति से बढ़ती जनसंख्या @ 1.8% वार्षिक वृद्धि, जो अब 125 करोड़ को पार कर गई है, को रोटी, कपड़ा, और मकान की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा, जिसमें ड्रिप, फुव्वारी एवं पाइप सिस्टम पद्धतियों; जीवांश/जैविक खेती, फसल चक्र के सिद्धान्तों को अर्थात् फसल विविधीकरण; फर्टीगेशन, वर्षा जल संरक्षण को विशेष महत्व देखकर अपनाना होगा।

सन्दर्भ सूची :-

1. अग्रवाल, जी0के0 एवं पाण्डेय, एस0एस0 : 'ग्रामीण समाजशास्त्र' साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा0लि0, आगरा, 2004, पृ0 494-198 ।
2. पाण्डेय, एस0एस0 : 'समाजशास्त्र' टाटा मैकग्रा-हिल एजुकेशन प्रा0लि0, 7, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली, पृ0 12.13-12.15 ।
3. प्रतियोगिता दर्पण : हिन्दी मासिक पत्रिका, अंक- जून 2015, पृ0 100 ।
4. मिश्र, एस0के0 एवं पुरी, वी0के : 'भारतीय अर्थव्यवस्था', 2001, पृ0 333 ।
5. शर्मा, देविन्दर : "'किसानों के हित में फ़ैसला," लेख, दैनिक जागरण, हिन्दी समाचार पत्र , लखनऊ, अंक 03 सितम्बर 2015 ।
6. सुरेका, मूंगालाल : 'ग्रामीण भारत,' नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1999, पृ0 1 ।
7. देशाई, ए0आर0 : 'भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र,' कृषिक अर्थशास्त्र की भारतीय संस्था, बम्बई, 1959, पृ0 62 ।
8. बिताई, आन्द्रे : 'स्टडीज इन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर', थामसन प्रेस (इण्डिया) फरीदाबाद, 1997, पृ0 29 ।
9. स्मिथ, टी0 लिन0 : 'दि सोशियॉलाजी ऑफ रूरल लाइफ' हार्पर एण्ड ब्रास , न्यूयार्क, 1998, पृ0 10 ।
10. नेल्सन, लॉरी : 'रूरल सोशियॉलाजी- डायमेन्शन एण्ड होरिजेन्स', सेज पब्लिकेशन इण्डिया, प्रा0लि0, नई दिल्ली 1945, पृ0 18 ।